



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
भारत सरकार  
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट  
2015-16





हरित राजमार्ग

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  
(वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यीकरण और अनुरक्षण) नीति - 2015  
पर राष्ट्रीय सम्मेलन एवं नीति की उद्घोषणा  
द्वारा

श्री नितिन गडकरी

(मंत्री सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

National Conference and Launch of

GREEN HIGHWAYS (PLANTATION, TRANSPLANTATION, BEAUTIFICATION & MAINTENANCE) POLICY - 2015  
by

Shri Nitin Gadkari

(Minister of Road Transport, Highways & Shipping)

29<sup>th</sup> September 2015, The Ashok, New Delhi

29 सितम्बर 2015, होटल अशोक, नई दिल्ली



हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यीकरण और अनुरक्षण) नीति 2015  
पर राष्ट्रीय सम्मेलन एवं नीति की उद्घोषणा



# वार्षिक रिपोर्ट 2015-16



भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
नई दिल्ली





रास्ता दीजिए  
Give Way

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यीकरण और अनुरक्षण) नीति 2015 पर राष्ट्रीय सम्मेलन एवं नीति की उद्घोषणा

इस चिन्ह का प्रयोग गोलचक्कर पर किया जाता है जहाँ एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दायीं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है।

This sign is used at roundabouts where a specific lane discipline is to be followed. This sign directs the traffic to give way to the fellow traffic on your right side.



## विषय-सूची

क्रम संख्या	अध्याय	पृष्ठ
I	परिचय	7
II	वर्ष एक नजर में	9
III	सड़क विकास	19
IV	सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा	35
V	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	45
VI	अनुसंधान और विकास	49
VII	राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल)	53
VIII	प्रशासन और वित्त	61
IX	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	73
X	निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन	75
XI	परिवहन अनुसंधान	77
XII	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	81
<b>परिशिष्ट</b>		
परिशिष्ट -1	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आबंटित विषय	85
परिशिष्ट -2	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना	87
परिशिष्ट -3	देश में राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची	88
परिशिष्ट - 4	वर्ष 2015-16 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुसंधान हेतु आवंटन	92
परिशिष्ट -5	केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आवंटन और निधियाँ जारी करना	94
परिशिष्ट- 6	अतिपरिमापित और अतिभारित कार्यों के लिए राज्यवार अनुमतियाँ	95
परिशिष्ट -7	वित्तीय प्रगति 2015-16, (एनएचआईडीसीएल)	96
परिशिष्ट -8	अनु. जाति/अनु. जनजाति कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों की संख्या (तकनीकी और गैर-तकनीकी)	97
परिशिष्ट -9	राष्ट्रीय परमिट शुल्क के राज्यवार संवितरण का विवरण	98
परिशिष्ट -10	मुख्य शीर्षवार व्यय	99
परिशिष्ट -11	राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय लेन-देन के अनुरूप निधियों के स्रोत	101
परिशिष्ट -12	पिछले तीन वर्षों के लिए राजस्व प्राप्तियों का शीर्षवार ब्यौरा	102
परिशिष्ट -13	लेखों के मुख्य बिंदु	103
परिशिष्ट -14	अशक्त व्यक्तियों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों की स्थिति	104

यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है। इसलिए, चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए।

This sign notifies that entry is prohibited for all vehicles. Certain pockets of an area or road are demarcated as 'no entry' areas for traffic. This could be entry to a restricted area or no-traffic zone. So the driver should obey it and divert his route.





चौड़ाई सीमा  
Width Limit



क्रम संख्या	परिशिष्ट	पृष्ठ
परिशिष्ट -15	भारत में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या : 2003 से 2013	105
परिशिष्ट -16	सड़क दुर्घटनाओं में घायल और मारे गये व्यक्तियों की संख्या : 2003 से 2014	106
परिशिष्ट -17	श्रेणीवार सड़क नेटवर्क : 1951 से 2013	107



हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यीकरण और अनुरक्षण) नीति 2015 पर  
राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित प्रतिभागी

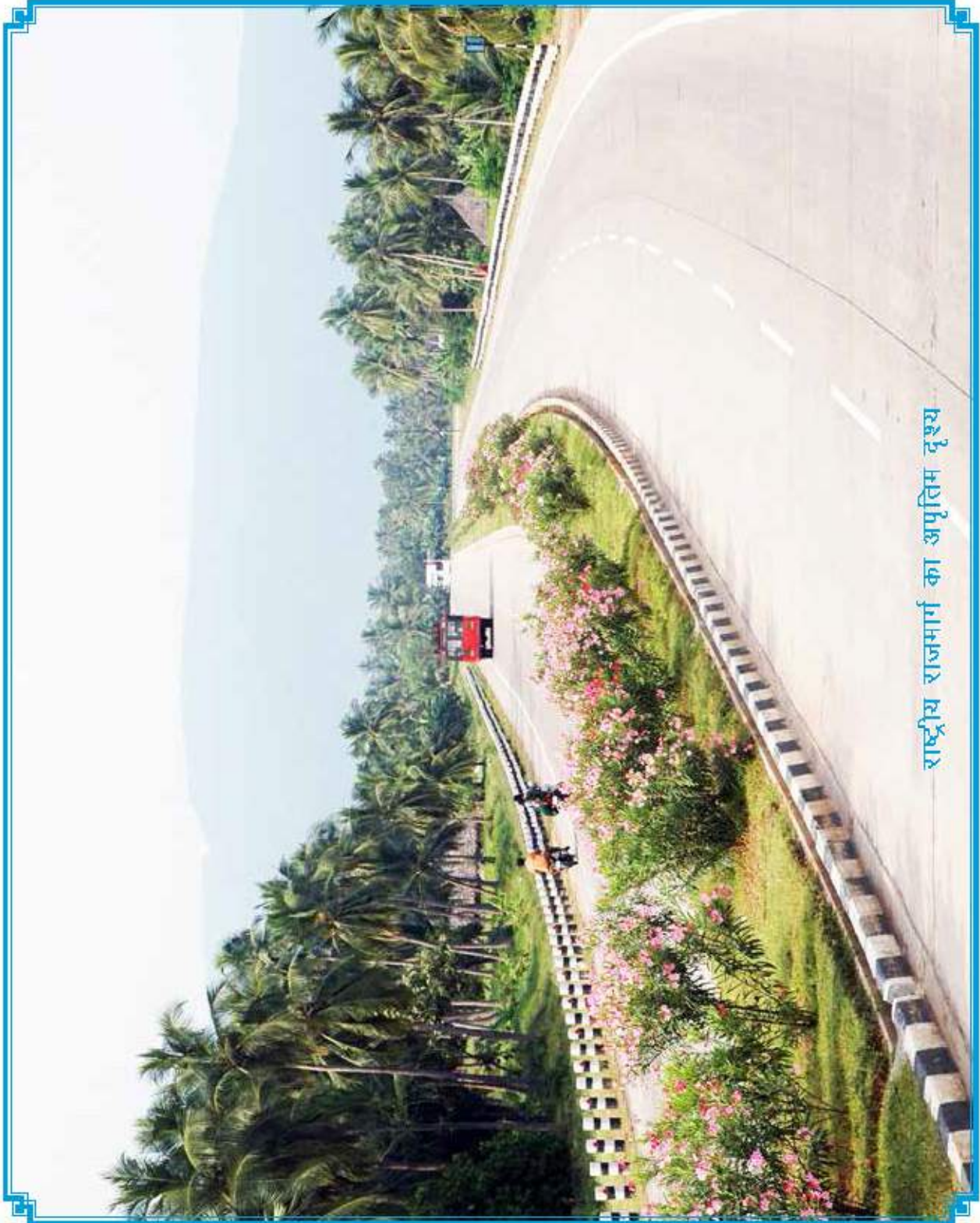
यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।

This sign indicates the width of the vehicle, which is allowed to enter the zone beyond it. The vehicle with width above 2 meters is restricted to enter this zone. This could be a bridge or a narrow lane.





सभी मोटर वाहनों  
का आना मना है  
All Motor  
Vehicles Prohibited



राष्ट्रीय राजमार्ग का अपृतिम दृश्य

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़-भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है।

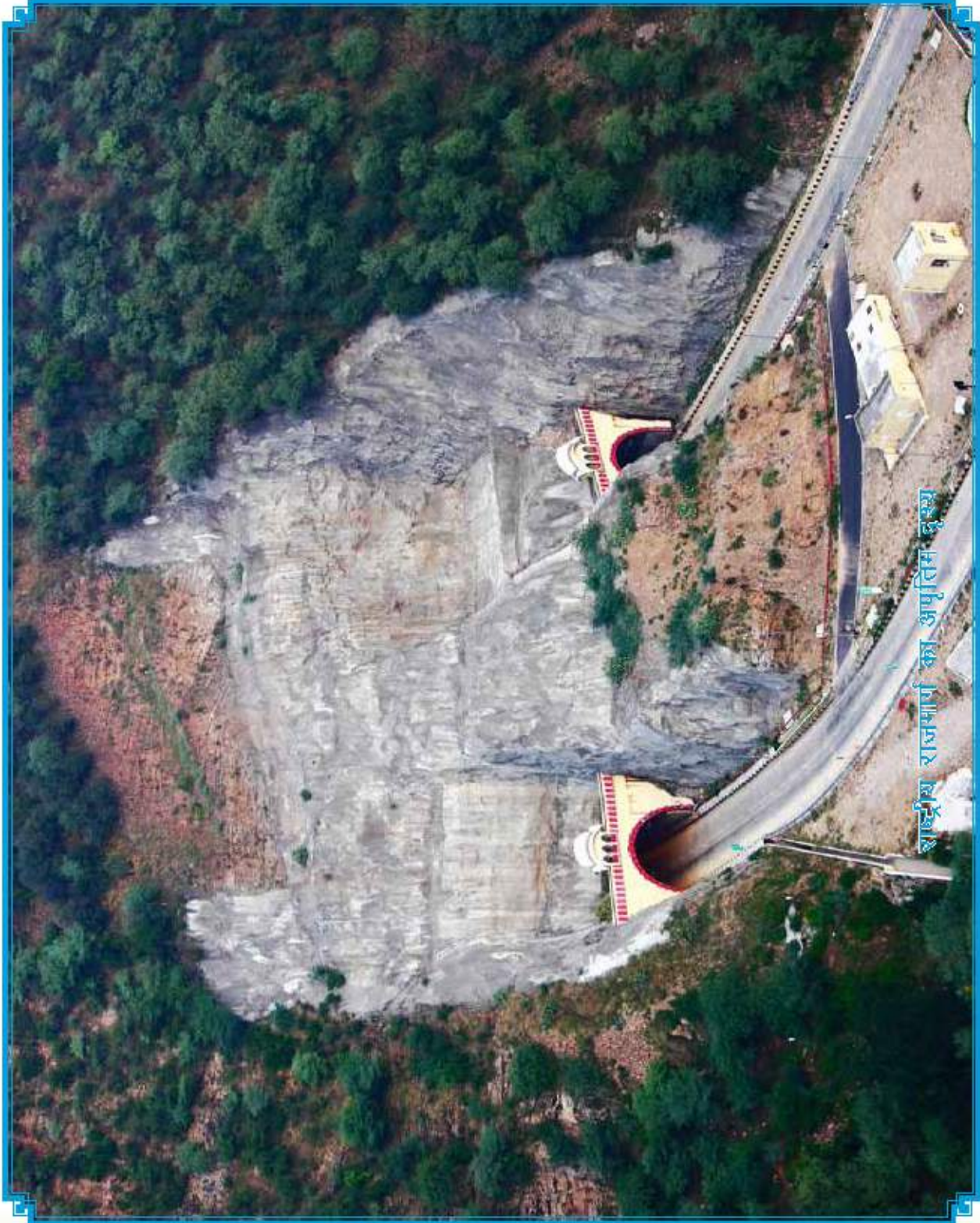
This sign signifies that there should be no movement of traffic in the designated area either from outside or within. This is used to decongest the area. It is also used at pedestrian areas.





ट्रकों का आना मना है  
Truck Prohibited

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों (एचएमवी) का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है।

As sign itself speaks the area designated is a no entry zone for Trucks or HMV. These could be narrow lanes or congested areas where entry of heavy transport vehicle could obstruct smooth flow of traffic.





## अध्याय-I

### प्रस्तावना

- 1.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का वर्ष 2009 में गठन पूर्ववर्ती नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था ।
- 1.2 देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन एक जटिल अवसंरचना है । यह विकास की गति, संरचना और पद्धति को प्रभावित करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुक्षण, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के प्रशासन, सड़क परिवहन, पर्यावरण संबंधी मामलों, ऑटोमोटिव मानकों, राष्ट्रीय राजमार्गों इत्यादि के प्रयोग हेतु प्रयोक्ता फीस दर निर्धारित करने आदि के अलावा पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन की व्यवस्था करने का कार्य करता है।
- 1.3 यातायात (यात्री और कारगो) को संभालने के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता औद्योगिक विकास की वृद्धिशील अपेक्षाओं की गति के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। भारत का सड़क नेटवर्क 52.32 लाख कि.मी. है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस मार्ग, राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं जिनकी लंबाई निम्नवत है :

राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्ग	1,00,475 कि.मी.
राज्यीय राजमार्ग	1,48,256 कि.मी.
अन्य सड़कें	49,83,579 कि.मी.

- 1.4 ऐतिहासिक तौर पर, परिवहन क्षेत्र में निवेश सरकार द्वारा ही किया जाता रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं ।

### कार्य

- 1.5 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आवंटित विषयों को परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध किया गया है ।

### संगठन

- 1.6 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना परिशिष्ट-2 में दी गई है ।

### 1.7 सम्बद्ध कार्यालय

#### 1.7.1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 1988 नामक एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था । यह इसको सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुक्षण और प्रबंधन तथा उनसे जुड़े अथवा उनके प्रासंगिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है । यह प्राधिकरण फरवरी, 1995 से प्रचालन में है ।

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ-ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं ।

This sign indicates that the road has been prohibited for plying of Bullock & Hand Carts. These slow moving carts many a times hinder the smooth flow of traffic.





लंबाई सीमा  
Length Limit



### 1.7.2 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आई.ए.एच.ई.)

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आई.ए.एच.ई.) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पंजीकृत संस्था है। यह केंद्र और राज्य सरकारों का एक सहयोगी निकाय है जिसका वर्ष 1983 में गठन देश में राजमार्ग अभियंताओं के प्रवेश स्तर एवं सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण की दीर्घकाल से अनुभव की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी।

### 1.7.3 राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि. (एनएचआईडीसीएल)

मंत्रिमंडल ने 13.03.2014 को हुई अपनी बैठक में पड़ोसी देशों के साथ सतत आधार पर क्षेत्रीय सड़क सम्पर्क संवर्धित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले पड़ोसी देशों के समीपस्थ देश के भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/उन्नयन/चौड़ीकरण का कार्य विशिष्ट रूप से किए जाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कारपोरेट संस्था को स्थापित करने तथा उसे प्रचालनात्मक बनाने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया।



राष्ट्रीय राजमार्ग का अपूर्तिम दृश्य

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित बंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.





## अध्याय-II

### वर्ष 2015-16 एक नजर में

#### (क) सड़क विकास

##### सड़क नेटवर्क

#### 2.1 सड़क क्षेत्र: 31 दिसम्बर, 2015 तक विभिन्न कार्यक्रमों की स्थिति निम्नानुसार है :

चरण	कुल लम्बाई कि.मी. में	31.12.2015 तक पूर्ण की गई लम्बाई कि.मी. में	1.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान पूर्ण की गई लम्बाई
एनएचडीपी-I जीक्यू ईडब्ल्यू-एनएस कोरिडोर पत्तन संपर्क और अन्य	7,522	7521	1
एनएचडीपी-II उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम कोरिडोर व अन्य को 4/6 लेन का बनाना	6,647	5903	48
एनएचडीपी-III उन्नयन, 4/6 लेनिंग बनाना	12,109	6734	252
एनएचडीपी-IV पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेनिंग बनाना	20,000	1825	709
एनएचडीपी-V जीक्यू और उच्च सघनता कोरिडोर को 6 लेनिंग बनाना	6,500	2319	223
एनएचडीपी-VI एक्सप्रेसवे	1000	-	-
एनएचडीपी-VII रिंग रोड, बाईपास और पलाईओवर एवं अन्य अवसंरचनाएं	रिंग रोड/बाईपास पलाईओवर इत्यादि 700 कि.मी.	22	-
एसएआरडीपी-एनई	6190	1829	82
एलडब्ल्यूई	5422	3904	334
एनएचआईआईपी	1120	239.16	157

**गैर-एनएचडीपी:** मौजूदा वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक इस योजना के अंतर्गत 120 कि.मी. लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक मौजूदा भुगतानों के अनुसार 615 कि.मी. सड़क सुदृढीकरण और 518 कि.मी. सड़क का इम्प्रूविंग राईड क्वालिटी प्रोग्राम (आईआरक्यूपी) के अंतर्गत निर्माण किया गया है।

आम तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं।

This sign is usually installed before a bridge. It indicates the load that a bridge can bear. The limit of this sign is 4 tonnes which indicates that only vehicles with axle load of 4 tonnes or less can pass over the bridge.





हाथ चेलों का आना मना है  
Hand Cart Prohibited

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



### 2.1.1 सड़क रकंध द्वारा की गई मुख्य पहलें:

मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित मुख्य पहलें की गई हैं—

1. क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-मुगतान पद्धति का कार्यान्वयन अथवा आनलाइन प्रत्यक्ष मुगतान प्रक्रिया ।
2. खुदरा आउटलेटों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के लिए आनलाइन आवेदन सुविधा और ओएफसी केबल आदि के लिए अनुमति जारी करना ।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का वेब आधारित अनुवीक्षण ।
4. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें उनक अडचनों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो जीएडी प्रक्रिया के अनुमोदन और निर्माण के दौरान आड़े आती थीं। समझौता ज्ञापन आरओबी के जीएडी अनुमोदन को सुगम बनाएगा और इससे आरओबी के निष्पादन के दौरान निर्णय लेने में भी सहायता मिलेगी।
5. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने समयबद्ध रीति से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी स्तरों के क्रॉसिंग्स को आरओबी/आरयूबी द्वारा हटाने का निर्णय लिया है।
6. मंत्रालय ने एचटी-3 श्रेणी तक के हाइड्रॉलिक ट्रेलरों की आवाजाही के लिए अनुमति देने हेतु एक वेब पोर्टल विकसित किया है और 6 जनवरी, 2015 को इसका शुभारम्भ किया गया है। इस वेब पोर्टल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाइड्रॉलिक ट्रेलरों की आवाजाही के लिए सही समय पर अनुमति प्राप्त करने में सुगमता होगी। इससे भारी उपकरणों की सूचारु और समय पर आवाजाही में आसानी होगी जिससे राष्ट्र का आर्थिक विकास होगा।
7. राज्यवार प्राधिकारी अभियंताओं की नियुक्ति की गई है जो मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित सिविल कार्यों का ईपीसी दस्तावेजों के अनुसार पर्यवेक्षण करेंगे।
8. मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के लिए इन्वेंटराइजेशन और कंडीशन सर्वे पूरा करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया में है। यह परामर्शदाता आईआरसी:एसपी:35 के अनुसार आवधिक रूप से कंडीशन सर्वे करेंगे। इन परामर्शदाता द्वारा संग्रहीत डेटा को आईएएचई, नोएडा द्वारा स्थापित किये जा रहे पुल प्रबंधन केंद्र द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा जो मंत्रालय को भावी योजना और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध निधियों में से पुल परिसम्पत्तियों की प्राथमिकता के संबंध में सुझाव देगा।

### आईएचई



राष्ट्रीय राजमार्ग का संपूर्ण दृश्य

यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ चले चलाने पर रोक है क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं।

This sign indicates that the Hand Cart is prohibited on the demarcated road as it would hinder the flow of fast moving traffic.





आईएचई में प्रशिक्षण कार्यक्रम



राजमार्ग क्षेत्र के हितधारकों के साथ इंटरैक्टिव सत्र

साइकिल-सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर, जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए, साइकिल-सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जहां यह चिन्ह लगा हो।

In order to ensure the safety of cyclists certain roads which are meant for fast moving vehicles are prohibited for cyclists. So the cyclists should not use the roads where this sign has been installed.





गति सीमा  
Speed Limit

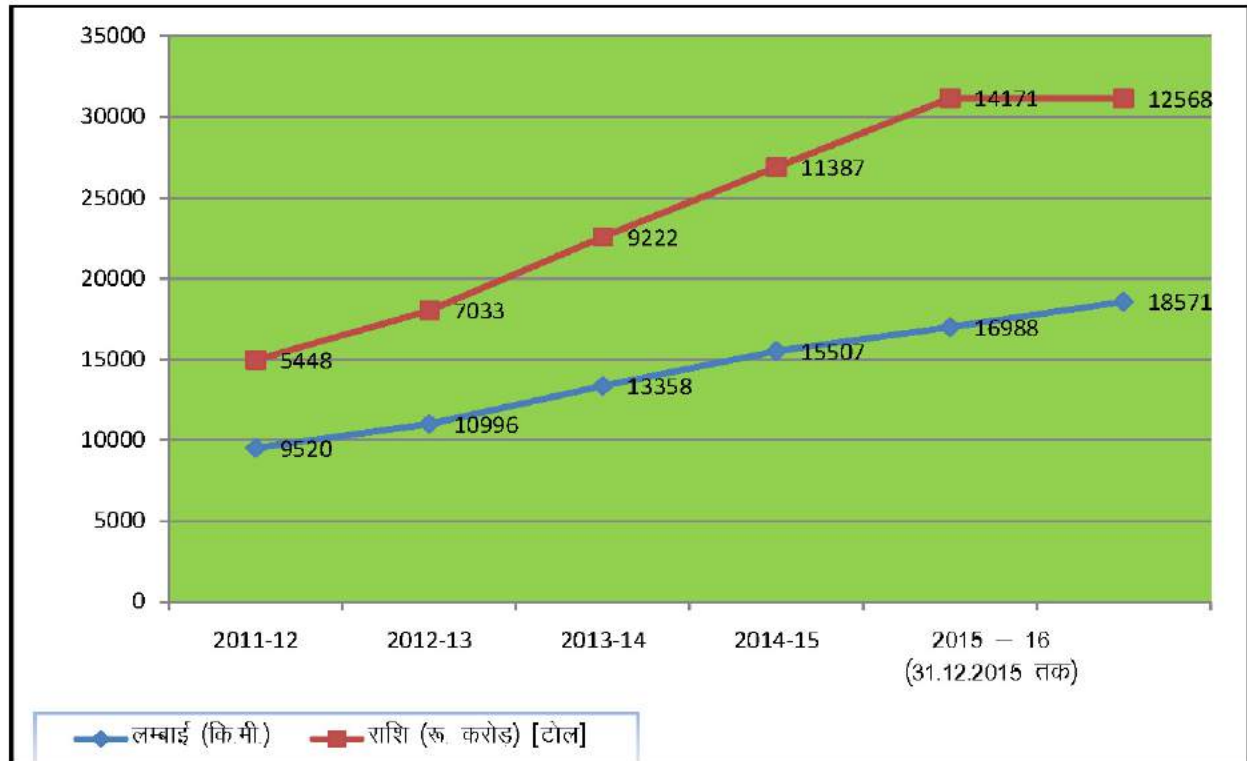


2.2 चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 1231 इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 68 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

#### 2.4 पथकर प्रभाग द्वारा की गई प्रमुख पहलें:

2.4.1 राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुचारु आवागमन के लिए माननीय सांसदों को तीन "फास्टैग" दिये जाएंगे।

2.4.2 शुल्क योग्य लम्बाई और संग्रहीत शुल्क के ब्यौरे इस प्रकार हैं:



#### 2.4.3 आटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर और क्लासीफायर (एटीसीसी) का इस्तेमाल किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात सर्वेक्षण

यातायात के आंकड़े राजमार्ग विकास और योजना के लिए अनिवार्य घटकों में से एक होते हैं । यातायात की मात्रा राजमार्ग के किसी खंड में लेनों की संख्या, बीओटी (पथकर) और बीओटी (वार्षिकी) परियोजनाओं के लिए रियायत अवधि, राजमार्गों के किनारे सुविधाओं और वर्तमान एवं भावी विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का निर्णय करती है । क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों अथवा स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से हाथ से किए गए यातायात सर्वेक्षणों द्वारा यातायात आंकड़ों के संग्रहण का परम्परागत तरीका वैज्ञानिक नहीं है और इसका मानकीकरण किए जाने की आवश्यकता है । राजमार्ग परियोजनाओं के लिए विशुद्ध यातायात सर्वेक्षण और अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की सम्पूर्ण लम्बाई पर एटीसीसी का इस्तेमाल करके योजना और व्यवहार्यता अध्ययन, यातायात सर्वेक्षण किया जाएगा ।

सभी पथकर प्लाजाओं पर एक ऐसी पद्धति होनी चाहिए जो सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सम्पूर्ण लम्बाई पर यातायात का सम्पूर्ण यातायात सर्वेक्षण करने के लिए वाहन की श्रेणी और उसके आकार

यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है, जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शायी जाती है। दंडात्मक कार्यवाही और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए।

This sign designates the speed of traffic on road. The limit specified must be invariably followed to avoid penal action and crashes on the road.





की पहचान कर सके। एटीसीसी लगाने के लिए सम्पूर्ण भारत में 1610 स्थान अभिज्ञात किए गए हैं। यातायात सर्वेक्षण करने के लिए देश को 7 जोनों में विभाजित किया गया है। यातायात सर्वेक्षण छमाही आधार पर किया जाएगा। यातायात सर्वेक्षण का अनुवीक्षण करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष होगा। यह राजमार्ग परियोजनाओं, योजना और व्यवहार्यता अध्ययन के लिए वास्तविक अनुमान लगाने में सहायता करेगा। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और यातायात सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है। पहले चरण में दिसम्बर, 2015 तक 1524 सर्वेक्षण पूरे किये गये हैं। दूसरे चरण में जनवरी, 2016 तक 223 सर्वेक्षण पूरे किये गये हैं।

#### 2.4.4 इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली

बाधाओं को दूर करने और यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने तथा विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार टोल संग्रहण करने के लिए पेशिव रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैक्नोलॉजी (आरएफआईडी) का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

इंडियन हाइवेज मैनेजमेंट कम्पनी लि. (आईएचएमसीएल) और आईसीआईसीआई बैंक तथा एक्सिस बैंक के बीच इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) के लिए सेंट्रल क्लियरिंग हाउस (सीसीएच) हेतु सेवा प्रदाता समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

मार्च, 2016 तक अखिल भारतीय स्तर पर ईटीस प्रणाली क्रियान्वित की जाएगी।

#### 2.4.4 आटोमेटिक व्हीकल काउंटर एंड क्लासीफायर (एवीसीसी) प्रणाली

एवीसीसी प्रणाली लेनों से गुजरने वाले वाहनों का वर्गीकरण और उनकी गिनती करती है। इसका इस्तेमाल पथकर संग्रहण के लिए संपरीक्षा के रूप में भी किया जाता है। पथकर प्रबंधन प्रणाली पथकर संग्रहणकर्ता द्वारा प्रविष्ट की गई एवीसीसी की श्रेणी और वर्गीकरण की जांच करती है। यदि उनमें कोई मिलान न हो तब लेन कैमरा श्रेणी विषमता संदेश, तारीख और समय सहित प्रविष्टी संख्या, लेन संख्या और पथकर संग्रहणकर्ता के ब्यौरे के साथ वाहन की डिजिटल छवि ले लेता है। छवि और विषमता संबंधी सूचना पथकर पर्यवेक्षण स्टाफ द्वारा आगे संसाधित किए जाने के लिए पर्यवेक्षण दल को संसूचित की जाएगी। गिनती और वर्गीकरण संबंधी आंकड़ों को दूर से ही सीधे दर्ज किया जा सकता है।

इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है ताकि सभी पथकर प्लाजाओं पर इस प्रणाली को कार्यान्वित किया जा सके।

#### 2.4.5 वे-इन मोशन ब्रिज (डब्ल्यूआईएम) प्रणाली

वाहनों में अतिभार लदान न केवल राजमार्गों के आर्थिक जीवन और उन सड़कों के लिए क्षतिकारक है जिन पर यांत्रिक वाहन चलते हैं बल्कि उनसे सुरक्षा संबंधी मुद्दें भी बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं।

मोटरयान अधिनियम, 1988 और राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस) नियमावली, 2008 के प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर वे-इन मोशन ब्रिज स्थापित किए जाने हैं।

यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़ें।

This sign directs driver not to turn towards right side in any circumstance.





बाएं मुड़ना मना है  
Left Turn Prohibited



#### 2.4.6 सीसीटीवी निगरानी प्रणाली

सभी टोल प्लाजाओं पर आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। सीसीटीवी प्रणाली का प्रयोग लेन एरिया और प्लाजा ब्लिडिंग क्षेत्रों की निगरानी के लिए किया जाएगा। सभी टोल प्लाजाओं से प्राप्त वीडियो की ऑन लाइन निगरानी के लिए नियंत्रण केंद्र पर वीडियो मॉनिटर/वीडियो वॉल लगाये जाएंगे।

आवश्यक कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी गई है ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल प्लाजाओं में यह प्रणाली उपलब्ध हो सके। इस कार्य को चार अंचलों में विभाजित किया गया है और सविदाओं पर इस्ताफ़र हो चुके हैं। डब्ल्यूआईएम और सीसीटीवी निगरानी 6 अवस्थानों पर स्थापित कर दी गई है।



#### ख सड़क परिवहन क्षेत्र

2.4.7 सभी राज्यों में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा प्रयोग किये जाने हेतु व्यापक प्रवर्तन समाधान के लिए एक मोबाइल एप्प सह वेब एप्लीकेशन विकसित किया गया है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए व्यापक प्रवर्तन समाधान हेतु मोबाइल सह वेब एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। परिवहन डेटाबेस से विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रणालियों जैसे कि वेब सेवाएं, सुरक्षित लॉग-इन, पुल-एसएमएस, बल्क ट्रान्सफर के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं जैसे कि सरकारी विभागों, पुलिस, छंटनी करनी वाली एजेंसियों, बैंकों और इश्योरेंस कंपनियों, ट्रान्सपोर्टों और सामान्य नागरिकों को डेटा पहुंच सुविधा प्रदान की गई है।

2.4.8 अब वितरित 'वाहन' और 'सारथी' वर्जनों के स्थान पर एक नई केंद्रीकृत वेब-युक्त एप्लीकेशन को विकसित किया गया है जिसमें सड़क परिवहन कार्यालयों से संबंधित संचालन के सभी पहलू/व्यापार केंद्रित सेवाएं शामिल हैं। सभी आधुनिक विशेषताओं और कार्यात्मकताओं सहित 'वाहन' और 'सारथी' के इस नये वर्जन को एनआईसी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर उपलब्ध करा दिया गया है और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए खोल दिया गया है। पहले वर्जन से नए प्लेटफॉर्म पर डेटा अंतरण का कार्य भी पूर्णतया प्रगति पर है। 5 राज्यों में 25 सड़क परिवहन कार्यालयों में पहले ही नया वाहन वर्जन 4 रोलआउट

यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े।

This sign indicates that left turn is prohibited.





हो चुका है। 11 राज्यों के लगभग 60 सड़क परिवहन कार्यालयों में सांख्यिकी वर्जन 4 क्रियान्वित किया गया है। देश भर के सभी सड़क परिवहन कार्यालयों में इस वर्ष के अंत तक डेटा अंतरण का कार्य चलेगा।

- 2.4.9 मंत्रालय ने ई-रिक्शाओं और इसकी विनिर्दिष्टियों को केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत शामिल करने के लिए मोटर वाहन नियमावली, 1989 (केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली) में संशोधन हेतु दिनांक 08.10.2014 के सा.का.नि. 709 (अ), 08.10.2014 के का.आ. 2590 (अ) और दिनांक 13.01.2015 के सा.का. नि. 27 (अ) को अधिसूचित किया है जिसे मंत्रालय की वेबसाइट [www-morth-nic-in](http://www.morth-nic.in) पर अपलोड कर दिया गया है। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में मौजूदा ई-रिक्शाओं को नियमित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का उल्लेख है।
- 2.4.10 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 'मोटर यान अधिनियम, 1988' के स्थान पर 'सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक-2015' एक नये अधिनियम को लाने के प्रस्ताव पर कार्य कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और राष्ट्रीय परिवहन प्राधिकरण को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव है जिसमें सड़क सुरक्षा के लिए इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रवर्तन, मॉनिटरिंग और आपातकालीन उपचार मानकों का ध्यान रखा जाएगा। इस विधेयक में उन प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया गया है जो सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रणाली के सक्षम प्रयोग के प्रतिकूल हैं। इसमें परिवहन क्षेत्र की दक्षता में सुधार हेतु मल्टी मॉडल समन्वयन प्राधिकार लाने का भी प्रस्ताव है।

सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2015 का अद्यतन वर्जन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनकी टिप्पणियां/विचार प्राप्त करने के लिए 4 जून, 2015 को भेजा गया था। अब तक लगभग 26 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी टिप्पणियों भेजी हैं। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी टिप्पणियां/सुझाव अभी प्राप्त होने हैं, उन्हें अनुस्मारक भेजा गया है। सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2015 मंत्रालय की वेबसाइट [www.morth.nic.in](http://www.morth.nic.in) पर अपलोड कर दिया गया है।

- 2.4.11 सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के लिए निःशुल्क उपचार 'स्वर्णिम घंटे' के दौरान, त्वरित और उपयुक्त चिकित्सा परिचर्या प्रदान करके दुर्घटना पीड़ितों की जिंदगियों को बचाने और इस प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में घातकताओं को कम करने के उद्देश्य से मंत्रालय में निम्नलिखित प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ की हैं:-

- राष्ट्रीय राजमार्ग (सारा) संख्या 8 का गुडगांव-जयपुर खंड (आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा क्रियान्वित)।
- राष्ट्रीय राजमार्ग (सारा) संख्या 8 का बडौदरा-मुम्बई खंड (इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. द्वारा क्रियान्वित)।
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 का रांची-रागांव-महुलिया खंड (आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा क्रियान्वित)।

इस परियोजना में ध्यान रखा गया है कि दुर्घटना पीड़ितों को प्रथम 48 घंटे अथवा 30000/- रुपए जो भी पहले हो, के लिए दुर्घटना स्थल से उपचार के लिए अस्पताल ले जाने और जहां कहीं आवश्यक हो सरकारी अथवा प्राइवेट, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाया जाए ताकि दुर्घटना पीड़ितों को 'स्वर्णिम घंटे' के दौरान त्वरित और उपयुक्त चिकित्सा परिचर्या प्रदान करके उनके जीवन को बचाया जा सके।

प्रायोगिक परियोजना, समुचित अखिल भारतीय स्कीम को कार्यान्वित करने में मार्गनिर्देशन उपलब्ध कराएगी।

इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है।  
One has to turn towards left after seeing this sign. This may have been installed due to diversion.





आगे चलना अनिवार्य  
(केवल आगे)  
**Compulsory Ahead  
(Ahead Only)**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



प्रायोगिक परियोजना के परिणामों के आधार पर समूचे देश में सड़क दुर्घटना-पीड़ितों को नकदी रहित उपचार देने की स्कीम को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रायोगिक परियोजना के दौरान एकत्रित अनुभव और डेटा निम्नलिखित निष्कर्ष देंगे—

- (क) साधारण चोटों (ख) गम्भीर चोटों के ईलाज पर होने वाला सम्भावित व्यय।
- यदि दुर्घटना पीड़ित 48 घंटों बाद भी छुड़ी दिये जाने के लिए फिट न हो तो ईलाज एवं व्यय पूर्ति से संबंधित तौर-तरीके।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली अपेक्षित निधियों की मात्रा।

- 2.4.12 परिवहन क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और नगर निगमों के परिवहन/यातायात विभाग के अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित करना। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सीआईआरटी पुणे, एआरएआई पुणे, ईएससीआई हैदराबाद, आईआरटीई फरीदाबाद, आईआईटी दिल्ली, पीसीआरए दिल्ली और आईआईपी देहरादून, नामक सात प्रमुख संस्थानों के माध्यम से राज्य परिवहन/परिवहन विभाग कार्मिकों के लिए 54 प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्वीकृत किये गये हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि सहभागियों को सड़क परिवहन क्षेत्र के सभी क्षेत्रों की जानकारी दी जा सके और वे उभरती चुनौतियों का सामना कर सकें। अब तक 47 प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किये जा चुके हैं। शेष 7 कार्यक्रम इस वित्त वर्ष के अंत तक आयोजित किये जाएंगे।
- 2.4.13 रेडियो फ्रीक्वेंसी संकेतक की फिटमेंटरू राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों और प्रवर्तन प्राधिकारियों को राष्ट्रीय रजिस्टर में उपलब्ध आंकड़ों तक पहुंच प्रदान कराई गई है जिससे कि उन सभी ड्राइविंग लाइसेंसों/पंजीकरण प्रमाणपत्रों का तत्काल सत्यापन सुलभ होगा, जिनको उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर से एसएमएस भेजकर डिजिटाइज कर दिया गया है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के अंतर्गत 'एम' और 'एन' श्रेणी के वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी) टैग लगाना अधिदेशित किया गया था। इससे इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण (ईटीसी) को सरल और कारगर बनाना सुगम हो जाएगा और इसका उपयोग विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए भी किया जा सकता है।
- 2.4.14 मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् (एनआरएससी) सड़क सुरक्षा के लिए शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् (एनआरएससी) का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अंतिम बार गठन 31.08.2015 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। को-आप्टिड संस्थागत/व्यक्तिगत सदस्यों की कार्य अवधि अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से दो वर्षों के लिए होती है। गजट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक कम से कम वर्ष में एक बार होनी चाहिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 22.2.2016 को आयोजित की गई है जिसमें इस विषय पर विस्तृत चर्चाएं हुईं।
- 2.4.15 भौगोलिक सानिध्य के आधार पर भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कम्पनी लि. (आईएचएमसीएल) ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन हेतु देश को चार अंचलों में विभाजित किया है। हाल ही में चार अंचलों में कॉल सेंटर स्थापित करने हेतु अधिप्रापण किया गया है और शेष दो अंचल निविदा संबंधी समस्याएं हल करने के उपरांत कवर किये जाएंगे।
- 2.4.16 देश भर में 11 से 17 जनवरी, 2016 तक 27वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस बार सड़क सुरक्षा का थीम था "सड़क सुरक्षा-अमल का समय"। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार किया गया और राज्यसंघ राज्य क्षेत्र सरकारों, एसोसिएशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट

यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है।

This sign indicates the traffic should move in straight direction and turning to either side would lead to penal action and safety hazard.





अंडरटेकिंग (एएसआरटीयू), सभी ऑटोमोबाइल संघों और एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स आदि को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया।

#### 2.4.17 हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यीकरण और अनुरक्षण) नीति, 2015

यह नीति समुदाय, किसानों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और वन विभाग के सहयोग से पर्यावरण अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है ताकि सतत तरीके से आर्थिक वृद्धि और विकास सुनिश्चित किया जा सके।

इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ वृक्षारोपण के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करना वायु प्रदूषण और धूल के प्रभावों को कम करना है क्योंकि वृक्षों और झाड़ियों को वायु प्रदूषकों के लिए प्राकृतिक उन्मूलक के रूप में जाना जाता है; गर्मी के दौरान तपती गर्म सड़कों पर अति आवश्यक छाया प्रदान करना; वाहनों की संख्या में वृद्धि की वजह से हमेशा बढ़ने वाले ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना; तटबंध ढलावों पर मिट्टी के कटाव को रोकना; आने वाले वाहनों की हेड लाइट की रोशनी को रोकना; हवा और आने वाले विकिरण के प्रभाव को कम करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित इंडियन हाइवेज मैनेजमेंट कम्पनी लि., राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए उत्तरदायी है।

सभी राजमार्ग परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत (टीपीसी) का 1% भाग पूल किया जाएगा और राजमार्ग पर वृक्षारोपण तथा रख-रखाव के लिए अलग से रखा जाएगा।

जो कोई भी वृक्षारोपण और उसके रख-रखाव में दिलचस्पी रखता हो, इसमें भाग ले सकता है। तथापि, संस्थागत ढांचा सुनिश्चित करने के लिए संगठित समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों, सरकारी विभागों और वृक्षारोपण के कार्यों में अनुभव प्राप्त निजी उपक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्ष लगाने के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों को निविदा की अनुमति होगी। निम्नलिखित प्रकार की एजेंसियों इसके लिए पात्र होंगी:-

- सरकारी अथवा निजी क्षेत्र की कम्पनियों
- सोसाइटी, ट्रस्ट अथवा गैर लाभ- प्राप्त प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी
- महासंघ/उत्पादक संगठन
- स्वयं सहायता समूह/ जल प्रयोक्ता संघ/ संयुक्त वन प्रबंधन समूह/संयुक्त दायित्व समूह जैसी अनौपचारिक एजेंसियों।

2.4.18 सड़क निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ने से मूल-भूत ढांचे में विकास के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2016 के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लगभग 9,280 कि.मी. सड़क लम्बाई (जिसमें 3,034 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं) का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल लगभग 3.78 करोड़ श्रम-दिवस और 4.76 श्रम-दिवस प्रति कि.मी. सृजित होने की सम्भावना है। मंत्रालय का 2016-17 के दौरान 10,000 कि.मी. की सड़क परियोजनाओं के निर्माण का लक्ष्य है जिससे लगभग 4 करोड़ श्रम-दिवस रोजगार सृजित होने की सम्भावना है।





चौड़ाई सीमा  
Width Limit

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



सड़क सुरक्षा पदयात्रा

यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।

This sign indicates the width of the vehicle, which is allowed to enter the zone beyond it. The vehicle with width above 2 meters is restricted to enter this zone. This could be a bridge or a narrow lane.

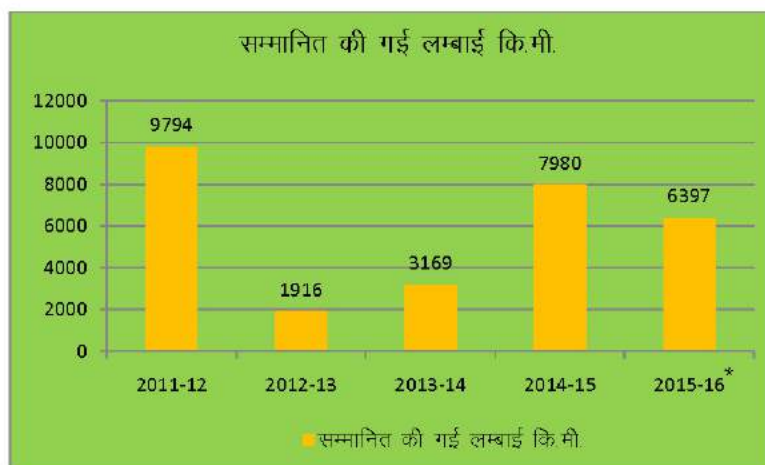




## अध्याय-III

### सड़क विकास

3.1 इस मंत्रालय को सामान्यतः सड़क परिवहन और राजमार्गों के विकास तथा विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुसूचना का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर राज्यों में सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राज्य सरकारों को राज्तीय सड़कों के विकास में सहायता देने के लिए केंद्र सरकार, केंद्रीय सड़क निधि, सीआरएफ और अंतर राज्तीय सम्पर्कता तथा आर्थिक महत्व (आईएससीएंडआई) योजना से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर सम्पर्कता सुधार कार्यक्रम (एनएचआईआईपी) की अतिरिक्त मंत्रालय एसएआरडीपी-एनई और एलडब्ल्यूई योजनाओं को भी क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्तीय सड़कें शामिल हैं। मंत्रालय सड़कों और पुलों के संबंध में तकनीकी सूचना के संग्रहालय के लिए कार्य करने के अतिरिक्त देश में सड़कों और पुलों के मानकों और विनिर्देशनों के निर्धारण के लिए भी उत्तरदायी है।



\* दिसम्बर 2015 तक

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है।

This sign directs the traffic to either move straight or take right turn. Turning towards left is prohibited.

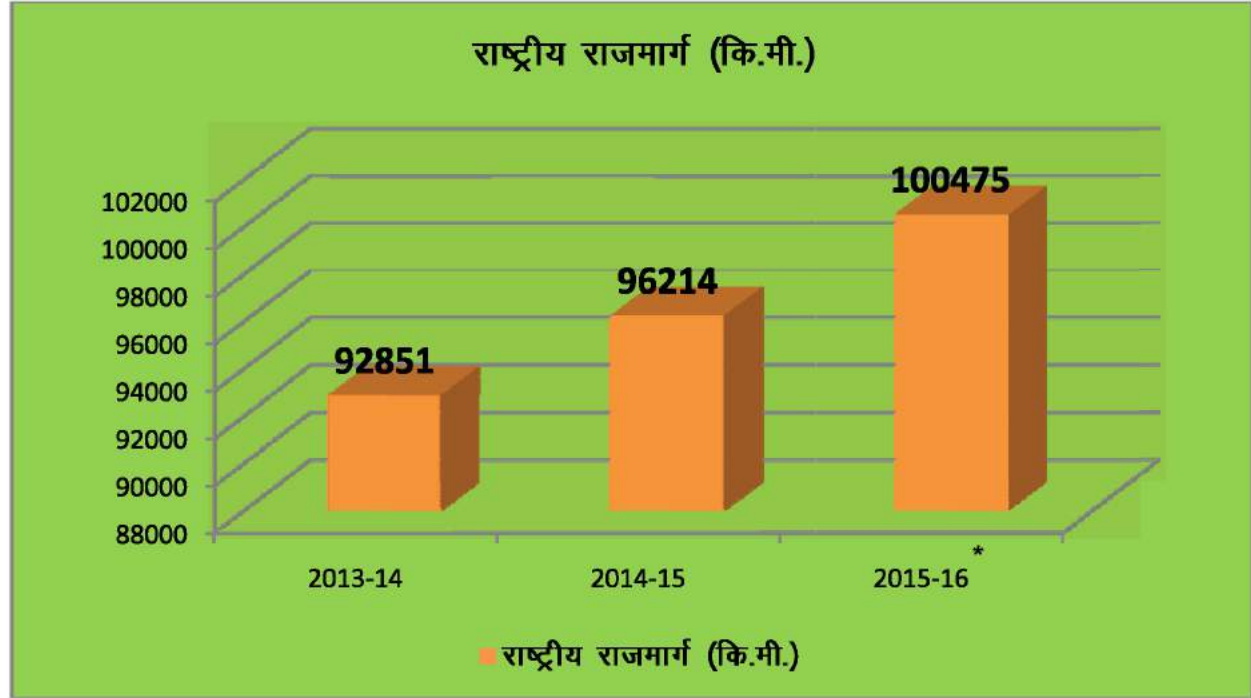




लंबाई सीमा  
Length Limit



- 3.2 राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 1,00,475 कि.मी. है जिसके लिए भारत सरकार संवैधानिक रूप से उत्तरदायी है। राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची परिशिष्ट-3 में दी गई है। विगत तीन वर्षों में निर्मित किये गये राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा इस प्रकार है:-



- 3.3 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में क्षमता दबाव, अपर्याप्त पेवमेंट क्रस्ट, घटिया ज्यामिती और सुरक्षा कारकों के अभाव जैसी विभिन्न कमियां हैं। उपलब्ध संसाधनों के अंदर, कार्यों को प्राथमिकताबद्ध करके विद्यमान राजमार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढीकरण, पुलों का पुनर्निर्माण/ चौड़ीकरण और बाइपासों का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जाता है। हालांकि, सरकार राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अधिक बजटीय आबंटन प्रदान कर रही है और उच्च सघनता वाले महामार्गों के उन्नयन के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, फिर भी राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त निधियां आबंटित कर पाना संभव नहीं हो पाया है। सड़क विकास के लिए अन्य स्रोतों से निधियां जुटाने के लिए संगठित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

### राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

- 3.4 सरकार ने एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है, जो देश में वर्ष 2000 से शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.





## राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

- 3.5 भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 6,00,000 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय वाली सात चरणों में फैली एक विशाल अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी है ।

## राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का वित्त-पोषण

- 3.6 वर्ष 2015-16 के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 89,301 करोड़ रुपए (सं.अ. 76,496 करोड़ रुपए) के व्यय का अनुमान लगाया है जिसमें से 73,032 करोड़ रुपए (सं.अ. 52,003 करोड़ रुपए) {{ वार्षिकी भुगतान, बाजार/भारत सरकार/एडीबी (प्रत्यक्ष) उधार और ब्याज राजमार्गों के अनुस्क्षण के लिए 12,271 करोड़ रुपए (सं.अ. 9157 करोड़ रुपए) ) सहित} भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बोर्ड से व्यय किये जाएंगे और 16,268 करोड़ रुपए (सं.अ. 24493 करोड़ रुपए) निजी क्षेत्र द्वारा व्यय किये जाने की संभावना है। दिसम्बर, 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निजी क्षेत्र दोनों ने संयुक्त रूप से 47,084.87 करोड़ रुपए व्यय किये। (ब.अ. 2015-16 का 52.73 प्रतिशत, जिसमें 3,766 करोड़ रुपए वार्षिकी भुगतान, बाजार/भारत सरकार/एडीबी (प्रत्यक्ष) उधार और ब्याज राजमार्गों के अनुस्क्षण के लिए शामिल हैं) जिसमें से 23,324 करोड़ रुपए सरकारी निधि से व्यय किये गये हैं और 17,542 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र द्वारा व्यय किये गये हैं ।
- 3.7 वित्त वर्ष 2015-16 के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उपकर के लिए 14,794 करोड़ रुपए (सं.अ. 18,420 करोड़ रुपए) और 11,535 करोड़ रुपए (बकाया 3,321 करोड़ रुपए सहित) (सं. अ. 6,500 करोड़ रुपए) पथकर संग्रहण, राजस्व भाग, ऋणात्मक अनुदान और प्रीमियम के एवज में भारत की समेकित निधि में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्लो बैंक निधि के रूप में जमा कराए गए हैं। एसएआरडीपी-एनई और जम्मू और कश्मीर परियोजनाओं के लिए 2,853 करोड़ रुपए (सं. अ. 2,706 करोड़ रुपए) पूर्वी परिधि एक्सप्रेसवे के लिए 200 करोड़ रुपए (सं.अ. 337 करोड़ रुपए) और राजमार्गों के अनुस्क्षण और मरम्मत के लिए 1327.26 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान 1158.05 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त बजटीय सहायता दी गई है।
- 3.8 बजट प्राक्कलन 2015-16 के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 54ईसी बांड और कर मुक्त बांड के माध्यम से 42,694.50 करोड़ रुपए (सं.अ. 23,000 करोड़ रुपए) जुटाने थे। दिसम्बर, 2015 तक 54ईसी बांड के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 6516.41 करोड़ रुपए जुटाये गये हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कर मुक्त बांड आवेदनों से 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त किये हैं, जिनका आवंटन अभी किया जाना है।

## राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण- I और II:

- 3.9 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण- I और चरण- II में निम्नलिखित मार्गों का 4/6 लेन के मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में विकास करना शामिल है:-
- (क) स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू) जो चार महानगरों अर्थात् दिल्ली – मुम्बई – चेन्नै – कोलकाता को आपस में जोड़ता है ।
- (ख) उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग (एनएसईडब्ल्यू) जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सलेम से कोचीन से निकलते हुए सिलचर को पोखन्दर से जोड़ते हैं ।

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है। दाएं मुड़ना वर्जित है। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

This sign directs the traffic to either move straight or take left turn. Turning towards right is prohibited. Violation of these sign may jeopardize your safety and may also lead to penal action.





एक्सल भार सीमा  
Axle Load Limit

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



- (ग) देश के महापत्तनों को राष्ट्रीय राजमार्गों तक सड़क संपर्क प्रदान करना ।  
(घ) अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ।
- 3.10 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I को, 30,300 करोड़ रुपए (1999 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2000 में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज के 5,846 कि.मी., उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम महामार्गों के 981 कि.मी., पत्तन संपर्क के 356 कि.मी. और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 315 कि.मी. को मिलाकर कुल 7,522 कि.मी. शामिल हैं । वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2015 तक 2 कि.मी. में कार्य पूरा किया गया ।
- 3.11 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II को 34,339 करोड़ रुपए (2002 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2003 में अनुमोदित किया गया था । इसमें मुख्यतः, उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम महामार्ग (6,161 कि.मी.) और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 486 कि.मी. को मिलाकर कुल 6,647 कि.मी. लंबाई शामिल है । वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2015 तक 48 कि.मी. में कार्य पूरा किया गया ।

### राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III:

- 3.12 सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत 22,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मार्च, 2005 में निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर 4,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाने के लिए अनुमोदित किया है । बाद में, सरकार ने उन्नयन के लिए कार्यान्वयन हेतु 17.10.2006 और 12.04.2007 को 12,109 कि.मी. की कुल लंबाई के अतिरिक्त खंडों को अनुमोदित किया जिसके लिए 12,230 कि.मी. की लंबाई अभिनिर्धारित की गई है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत 80,626 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर 12,109 कि.मी. लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाने के लिए अनुमोदित किया जाना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत खंडों का अभिनिर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया गया है:-
- चरण I और II में शामिल न किए गए उच्च घनत्व वाले यातायात कॉरीडोर ।
  - राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण-I और II) के साथ राज्य राजधानियों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना ।
  - पर्यटन केन्द्रों और आर्थिक महत्व के स्थानों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना ।
- दिसम्बर, 2015 तक 12,109 कि.मी. के लक्ष्य के मुकाबले में 6734 कि.मी. लंबाई में 2/4 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा लिया गया है और 3313 कि.मी. लंबाई में कार्य चल रहा है । वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2015 तक 252 कि.मी. में कार्य पूरा कर लिया गया है ।



राष्ट्रीय राजमार्ग का अपूर्तिम दृश्य

आम तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है । यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है । इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है । यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं ।

This sign is usually installed before a bridge. It indicates the load that a bridge can bear. The limit of this sign is 4 tonnes which indicates that only vehicles with axle load of 4 tonnes or less can pass over the bridge.





राष्ट्रीय राजमार्ग का अपूर्तिम दृश्य

### राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण- IV

3.13 इस चरण में, सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर 78,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लगभग 20,000 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है। यह चरण जुलाई, 2008 माह में अनुमोदित किया गया था। इसमें से लगभग 13,203 कि.मी. की लंबाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। 31 दिसम्बर, 2015 तक 1825 कि.मी. लंबाई को पहले ही 2/4 लेन का बनाया जा चुका है और शेष 4704 कि.मी. लंबाई का कार्य कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2015 तक 709 कि.मी. का कार्य पूरा कर लिया गया है।

### राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण- V

3.14 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत (डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन आधार पर) मौजूदा 4 लेन वाले 6,500 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 41,210 करोड़ रुपए (2006 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से 6 लेन बनाए जाने के कार्य को अक्टूबर, 2006 में अनुमोदित किया गया था। 6 लेन बनाए जाने वाले 6,500 कि.मी. में स्वर्णिम चतुर्भुज के 5,700 कि.मी. और अन्य खंडों के 800 कि.मी. शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की 6,500 कि.मी. लंबाई में से 31 मार्च 2015 तक 2319 कि.मी. लंबाई में 6 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और 1756 कि.मी. में कार्य चल रहा है। वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2015 तक लगभग 223 कि.मी. में कार्य पूरा कर लिया गया है।

यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है, जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शायी जाती है। दंडात्मक कार्यवाही और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए।

This sign designates the speed of traffic on road. The limit specified must be invariably followed to avoid penal action and crashes on the road.





राष्ट्रीय राजमार्ग का अप्रुक्तिम दृश्य

### राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण – VI

3.15 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI में डिजाइन-निर्माण-वित्त-प्रचालन पद्धति का अनुसरण करके सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत 1000 कि.मी. लंबे पूर्णतः पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेस मार्गों के विकास की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-VI को 16,680 करोड़ रुपए (2006 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर नवंबर, 2006 में अनुमोदित किया गया था। इस चरण के लिए कुल 16,680 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जिसमें से 9,000 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से प्राप्त होंगे और साध्यता वित्त पोषण अंतर को पूरा करने तथा भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण, परामर्शी सेवाओं आदि की लागत को पूरा करने के लिए शेष 7,680 करोड़ रुपए सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे।

### राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII

3.16 सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII के अंतर्गत बीओटी (पथकर) विधि से 16,680 करोड़ रुपए (2007 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से दिसंबर, 2007 में स्वतंत्र रिंग रोडों, बाइपासों, ग्रेड सेपरेटर्स, फ्लाईओवरों, उत्थापित सड़कों, सुरंगों, सड़क उपरि पुलों, अंडरपासों, सर्विस रोडों आदि के निर्माण को अनुमोदित किया है। एनएचडीपी चरण-VII के अंतर्गत निम्नलिखित खंड अमिनिघारित किए गए हैं:-

- पीपीपीएसी द्वारा 04.08.2008 को 1485 करोड़ रु. की लागत पर तमिलनाडु राज्य में चैन्नई पत्तन से मदुरावोयल तक चार लेन उत्थापित सड़क के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। आरएफक्यू प्रस्ताव 17.10.2008 को प्राप्त हुए। परियोजना का कार्य 06.01.2009 को सौंपा गया था।
- बेंगलूरु में रारा 7 के डबल फ्लाईओवर से नवीन हवाई पत्तन तक (22 कि.मी.) 680 करोड़ रु. की लागत पर उन्नयन का प्रस्ताव। यह परियोजना कार्यान्वयनधीन है।

### राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन

3.17 मौजूदा वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 4207.56 करोड़ (सं.प्रा. 5506.56 करोड़ रुपए) और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए

यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ज़ाहूर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है, जहां बीच में विभाजक (डिवाइडर) नहीं होता और उसी सड़क पर वुतरफा यातायात प्रवाह रहता है।

This sign indicates that the driver should drive in left lane for smooth traffic flow. This sign is installed mainly on the roads which do not have divider in between and two way traffic flows on the same road.





रून्य रूप की राशि आवटित की गई है। 4207.56 करोड़ (सं.प्रा. 5506.56 करोड़ रूपए) के अलावा राज्य लोक निर्माण विभाग को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए स्थायी पुल शुल्क निधि में से 50 करोड़ रूपए की राशि आवटित की गई है।

- 3.18 वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुस्क्षण के लिए सीमा सड़क संगठन को आवटित 80 करोड़ रूपए के अलावा 2701.40 करोड़ रूपए (सं. प्रा. 2698.40 करोड़ रूपए) की राशि आवटित की गई है।
- 3.19 वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा अनुस्क्षण के लिए आवटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा परिशिष्ट-4 में दिया गया है।



राष्ट्रीय राजमार्ग का अंतिम दृश्य

### पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई)

- 3.20 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की राजधानियों के साथ, जिला मुख्यालयों और दूर-दराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में लगभग 7530 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों में दो/चार लेन बनाए जाने तथा राज्यीय सड़कों की लगभग 2611 कि.मी. लंबाई में दो लेन बनाए जाने/सुधार करने की परिकल्पना की गई है। इससे, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में 88 जिला मुख्यालयों को, कम से कम दो लेन की सड़कों के माध्यम से, राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ा जा सकेगा।

इस कार्यक्रम को चरण 'क' और चरण 'ख' तथा अरुणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज में विभाजित किया गया है।

#### चरण 'क' :

इस चरण में 21,769 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से सड़कों की 4099 कि.मी. लंबाई का सुधार कार्य शामिल है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की 3014 कि.मी. लंबाई और राज्यीय सड़कों की 1085 कि.मी. लंबाई शामिल

अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचालन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचालन प्रतिबंधित है।

Compulsory cycle track signifies that cyclists should compulsorily use this track. It also restricts the movement of any traffic except cyclist of the track.





बाएं मुड़ना अनिवार्य  
(दाएं यदि संकेत विपरीत है)  
**Compulsory Turn  
Left (Right if Symbol  
is Reversed)**



हैं। सड़कों की 4099 कि.मी. लंबाई में से 3213 कि.मी. लंबाई में 12,821 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के विकास कार्य, सीमा सड़क संगठन और राज्य लोक निर्माण विभाग और एनएचआईडीसीएल को सौंपे गए हैं। शेष 886 कि.मी. लंबाई में से 112 कि.मी. लंबाई में कार्य, बीओटी (वार्षिकी) आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 20 कि.मी. अरुणाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और 752 कि.मी. एनएचआईडीसीएल द्वारा किया जाएगा। उक्त 3213 कि.मी. लंबाई में से 2610 कि.मी. लंबाई की परियोजनाएं 14,070 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिसम्बर, 2015 तक संस्वीकृत की जा चुकी हैं। इसके अलावा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित 886 कि.मी. लंबाई में से सरकार ने 9,212 करोड़ रुपए की लागत पर कुल मिलाकर 462 कि.मी. लंबाई की परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन अनुमोदन दे दिया है। ये कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। चरण 'क' के पूरा होने की संभावित तारीख मार्च, 2017 है।

### चरण 'ख' :

इस चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों की 2,392 कि.मी. लंबाई को दो लेन का बनाया जाना और राज्यीय सड़कों की 1,331 कि.मी. लंबाई में दो लेन बनाना/सुधार करना शामिल है। चरण 'ख' के केवल डीपीआर तैयार करने हेतु ही अनुमोदित किया गया है।

### सड़कों एवं राजमार्गों के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज:

अरुणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज, जिसमें 2319 कि.मी. (2205 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 114 कि.मी. राज्य/जीएस सड़कें) लम्बे सड़क खंड शामिल हैं, को सरकार द्वारा 9/1/2009 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसमें से 776 कि.मी. में कार्य को बीओटी (वार्षिकी) आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और शेष 1543 कि.मी. के लिए कार्य को ईपीसी आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। दिसम्बर, 2015 तक 15,288 करोड़ रुपए की लागत से 1675 कि.मी. लंबाई के कार्य सौंप दिए गए हैं। शेष 644 कि.मी. के लिए प्राक्कलनों की जांच की जा रही है। डीपीआर की तैयारी/जांच की जा रही है।

### 3.21 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का विकास

सरकार ने 26.02.2009 को आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में इनके समग्र विकास के लिए 7300 करोड़ रुपए की लागत से 1126 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों और 4351 कि.मी. राज्यीय सड़कों (कुल 5477 कि.मी.) को 2 लेन में विकसित किए जाने के लिए सड़क आवश्यकता प्लान (आरआरपी) को अनुमोदित किया था। देश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास का दायित्व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंपा गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उक्त कार्यक्रम संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों के माध्यम से संस्वीकृत और कार्यान्वित कराए जाने के लिए मुख्य अभियंताओं के अधीन एलडब्ल्यूई प्रभाग गठित किया है। अब तक, 8585 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत पर 5422 कि.मी. लंबाई के लिए विस्तृत प्राक्कलनों की संस्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 7005 करोड़ रुपए की लागत पर 5263 कि.मी. लंबाई के निर्माण का कार्य सौंपा जा चुका है। 3904 कि.मी. में विकास कार्य जनवरी, 2016 तक पूरा हो चुका है और अब तक किया गया संवर्धी व्यय 5398 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों के विकास को मार्च, 2017 तक पूरा करना है, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें अभी सौंपा जाना है।

इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है।  
One has to turn towards left after seeing this sign. This may have been installed due to diversion.





### 3.22 विजयवाड़ा रांची मार्ग का विकास

1622 कि.मी. लंबे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित विजयवाड़ा रांची मार्ग में से किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य स्कीम में शामिल नहीं की गई ओडिशा में 600 कि.मी. (निचल लंबाई 594 कि.मी.) राज्तीय सड़कों के विकास को सरकार द्वारा 4 नवम्बर 2010 को 1200 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित किया गया है ।

अब तक, 1126 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत के कुल 594 कि.मी. लंबाई के समी 9 पैकेजों के लिए विस्तृत प्राक्कलन संस्वीकृत किए जा चुके हैं और सौंप दिए गए हैं । जनवरी, 2014 तक 550 करोड़ रुपए के संचित व्यय पर 288 कि.मी. लंबाई का विकास कार्य पूरा किया जा चुका है ।



राष्ट्रीय राजमार्ग का अपूर्तिम दृश्य

### राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संपर्क सुधार परियोजना (एनएचआईआईपी):

3.23 राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संपर्क सुधार परियोजना (एनएचआईआईपी) के चरण-। के अंतर्गत विश्व बैंक की ऋण सहायता से बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के एकल/ मध्यम लेन से 2 लेन/पेव्ड शोल्डर संरक्षण सहित 2 लेन में पुनर्वास और उन्नयन तथा खांडों का सुदृढीकरण किया जाना है । इस कार्यक्रम में 5193 करोड़ रु. (विश्व बैंक का हिस्सा – 500 मिलियन यूएस डॉलर) की धनराशि से 1120 कि.मी. की कुल लंबाई वाले 15 सिविल कार्य टैकों वाले 11 खांडों की परिकल्पना की गई है । मंत्रिमंडल ने 18.04.2013 को परियोजना को अनुमोदित किया। यह परियोजना मार्च, 2022 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है ।

यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है ।

This sign indicates the traffic should move in straight direction and turning to either side would lead to penal action and safety hazard.





आगे चलकर दाएं मुड़ना  
अनिवार्य (बाएं बधि संकेत विपरीत है)  
Compulsory Turn Right Ahead  
(Left H Symbol is  
Reversed)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



### परियोजना घटक:

#### घटक क: सड़क सुधार और अनुरक्षण

- राष्ट्रीय राजमार्ग खांड की 1120 कि.मी. लम्बाई का 2 लेन/पेव्ड रोललंडर सहित 2 लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन
- निर्माण के पश्चात 5 वर्ष की अवधि के लिए परिसंपत्तियों का निष्पादन आधारित अनुरक्षण

#### घटक ख: संस्थागत विकास घटक

- उद्यम संसाधन योजना प्रारम्भ करना
- मानक प्रचालन नियमों का विकास
- दर विश्लेषण के लिए 'लागत डाटा बेस' (राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य के लिए) और 'डाटा पुस्तिका सहित विभिन्न मानक संदर्भ सामग्री को अद्यतन बनाना
- आईटी आधारित सड़क सूचना पद्धति
- व्यापक परिसंपत्ति प्रबंधन पद्धति— जिसमें 3 परियोजना राज्यों में समी गैर-एनएचडीपी राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं ।

#### घटक ग: सड़क सुरक्षा

- सड़क सुरक्षा मानकों और प्रक्रिया संहिताओं की समीक्षा और उनको अद्यतन करना
- परियोजना राज्यों में सड़क दुर्घटना डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन और
- केन्द्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा क्षमता का सुदृढीकरण

मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित परियोजना लागत 5193 करोड़ रु. (सिविल निर्माण कार्य 3686.14 करोड़ रु., भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनःस्थापन— 451.98 करोड़ रु., पर्यावरण शमन— 50.84 करोड़ रु., जनउपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण— 83.47 करोड़ रु., निष्पादन आधारित अनुरक्षण—350.18 करोड़ रु.,

यह चिन्ह झाड़वर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम झाड़वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है।  
This sign directs the driver to turn right only. Obeying this sign will lead to safety and hassle free drive.





भौतिक आकस्मिकताएं— 103.21 करोड़ रु., लोक निर्माण विभाग को एजेसी प्रसार—121.09 करोड़ रु., पर्यवेक्षण एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं—121.09 करोड़ रु., संस्थागत विकास और सड़क सुरक्षा – 225 करोड़ रु.) ।

### ऋण विवरण

- घटक क: सड़क सुधार और अनुरक्षण घटक— 468.05 मि. अमरिकी डालर
- घटक ख: संस्थागत विकास घटक— 16.7 मि. अमरिकी डालर
- घटक ग: सड़क सुरक्षा— 14 मि. अमरिकी डालर
- फ्रंट एंड फीस— 1.25 मि. अमरिकी डालर
- 5 वर्ष की छूट अवधि सहित ऋण को 18 वर्षों में चुकाना



सड़क सुरक्षा पदयात्रा

### कार्यान्वयन प्रबंध

- ईएपी जोन को परियोजना के सभी पहलुओं के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लेना होगा जिनमें शामिल हैं न्यासिक, प्रापण, टेका अनुवीक्षण पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय तथा संस्थागत सुदृढीकरण ।
- परियोजना कार्यान्वयन के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सहित संबंधित राज्य सीई एनएच के अंतर्गत एसई की अध्यक्षता में परियोजना समन्वय यूनिट ।
- टेकों के कार्यान्वयन का दैनंदिन पर्यवेक्षण किए जाने के लिए प्रत्येक उप-परियोजना सड़क के लिए ईई की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन यूनिट ।

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है।

This sign directs the traffic to either move straight or take right turn. Turning towards left is prohibited.





आगे चलना या  
बाएं मुड़ना अनिवार्य  
**Compulsory Ahead  
or Turn Left**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



- वर्ष 2015-16 के लिए आंबटन: समकक्ष निधि के अंतर्गत 590 करोड़ रु. और सारा (मूल) के अंतर्गत 150 करोड़ रु. ।
- दिसम्बर, 2015 तक संचयी व्यय रु. 894.80 करोड़ रु. ।
- दिसम्बर, 2015 तक संचितरण के लिए पात्र सकल व्यय: 536.99 करोड़ रु. ।
- विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्तिरु 202.34 करोड़ रु. ।

### केन्द्रीय सड़क निधि

3.24 मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए 26185.44 करोड़ रु. का आंबटन किया गया है जिसका का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्तीय सड़कों के लिए अनुदान	2,910.00
अंतर्राज्तीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	355.35
राष्ट्रीय राजमार्ग	22920.09
<b>जोड़</b>	<b>26185.44</b>

- 3.25 केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों के आंबटन के लिए नियत की गई निधियां, विभिन्न राज्यों को, ईंधन की खपत के आधार पर 30% मान देते हुए और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 70% मान देते हुए आंबटित की जाती हैं ।
- 3.26 वर्ष 2000-01 से 2015-16 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सड़कों के लिए आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण परिशिष्ट-5 में दिया गया है ।

### केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्तीय सड़कों के लिए अनुमोदन

3.27 वर्ष 2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्तीय सड़कों के सुधार के लिए 510 करोड़ रुपए की लागत वाले 59 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें अंतर्राज्तीय सड़क संपर्क एवं आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित कार्य शामिल नहीं हैं ।

### अंतर्राज्तीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाएं

3.28 अंतर्राज्तीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाएं, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अधिनियमन से पहले ही विद्यमान थीं । उस समय, केन्द्रीय ऋण सहायता से केवल मामूली धनराशि वाले कार्यक्रम ही संस्वीकृत किए जाते थे । अब इस योजना को केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित कर दिया गया है ।

### अंतर्राज्तीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृति

3.29 वर्ष 2015-16 के दौरान, अंतर्राज्तीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत राज्तीय सड़कों के लिए 355.35 करोड़ रु की धनराशि निर्धारित की गई है ।

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है । दाएं मुड़ना वर्जित है । इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

This sign directs the traffic to either move straight or take left turn. Turning towards right is prohibited. Violation of these sign may jeopardize your safety and may also lead to penal action.





## भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी

### व्यापक कार्यकलाप :

- 3.30 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई), इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक रजिस्टर्ड सोसायटी है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सहयोगी निकाय है। देश में राजमार्ग इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1983 में इसकी स्थापना की गई थी।
- 3.31 यह संस्थान पिछले 32 वर्ष से प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है और अब 10 एकड़ में विकसित अपने स्वयं के परिसर, ए-5, सांस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर-62, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में 01 अक्टूबर, 2001 से अपना कार्य कर रहा है।
- 3.32 राजमार्ग इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा के केंद्र स्थापित करते हुए इस अकादमी के दृष्टिकोण और विषय-क्षेत्र को संवर्धित किया गया है। राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देने में यह संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के कार्यों में मोटे तौर पर निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:-
- (क) नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देना।
  - (ख) वरिष्ठ और मध्य स्तर के अभियंताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।
  - (ग) वरिष्ठ स्तर के अभियंताओं और प्रशासकों के लिए सड़क विकास में शामिल अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम चलाना।
  - (घ) राजमार्ग क्षेत्र में विशेष क्षेत्रों और नई प्रवृत्तियों में प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - (ङ) स्वदेशी और विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास।
  - (च) पीपीपी और ईपीसी इत्यादि के आधार पर अल्पकालिक कोर्स/प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजन करना, देश में सड़कों और राजमार्गों की आयोजना/डिजायन/निर्माण और प्रबंधन में सामूहिक अनुसंधान आयोजित करना तथा सड़क सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ विकसित करना।
- 3.33 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी ने अपने प्रारंभ से अब तक (31 दिसम्बर 2015 तक) 1186 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों में सड़क विकास के कार्य में लगे 27576 राजमार्ग अभियंताओं और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एनएचआई/एनएनआरडीए, विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र से होते हैं।

यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है, जहां बीच में विभाजक (डिवाइडर) नहीं होता और उसी सड़क पर दुतरफा यातायात प्रवाह रहता है।

This sign indicates that the driver should drive in left lane for smooth traffic flow. This sign is installed mainly on the roads which do not have divider in between and two way traffic flows on the same road.





## वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

3.34 वर्ष 2015-14 के दौरान (31 दिसम्बर, 2015 तक), अकादमी ने 68 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 1231 अभियंताओं ने और पेशेवरों ने भाग लिया।

## सड़क और पुल कार्यों में यांत्रिकीकरण तथा आधुनिक उपकरणों का प्रयोग

3.35 सड़क और पुल निर्माण कार्यों में यांत्रिकीकरण से गुणवत्ता में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों की बचत, पर्यावरण हितैषी प्रक्रिया, उच्च उत्पादकता, न्यूनतम यातायात विक्षोभ आदि के रूप में परिणाम प्राप्त हुए हैं। इससे कार्यों के निष्पादन में गति आई है और कार्य सुरक्षा में सुधार हुआ है। सड़क और पुल निर्माण कार्यों में यांत्रिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- i) ऑटोमेटिक ओवरलोड जांच और यातायात सर्वेक्षण: वे-इन-मोशन-कम-ऑटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर्स-कम-क्लासीफायर्स (डब्ल्यूआईएम-सह-80 सीसी) सिस्टम से अधिक भार लदान को रोकने और यातायात संबंधी आंकड़े एकत्र करने में सहायता मिलती है। कर्नाटक राज्य में हासन और कोपल स्थानों पर 2 प्रणालियों स्थापित एवं शुरु की गई हैं। राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में एक पद्धति स्थापित किए जाने, असम और पश्चिम बंगाल में सिविल कार्यों की स्थापना संबंधी कार्य प्रगति पर हैं और तमिलनाडु में आरंभ किया जा रहा है।
- ii) ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स(बीआईएस) और लीगल मेट्रोलॉजी (एमएल) प्रभाग के माध्यम से समस्त एप्लीकेशन को कवर करते हुए सड़क वाहनों के लिए वे-इन-मोशन सिस्टम के राष्ट्रीय मानक तैयार करने हेतु भारत और विदेशों से प्राप्त टिप्पणियों सहित समस्त एप्लीकेशनस को कवर करते हुए सड़क वाहनों के लिए वे-इन-मोशन सिस्टम के पूर्व मानकों का प्रारूप तैयार किया गया है और प्रारूप स्तर पर इसे उपभोक्ता मामलों के विभाग को भेजा गया है।
- iii) राजमार्ग उपकरण संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सभी स्टेकहोल्डरों अर्थात् प्राधिकरणों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं और उपकरण निर्माताओं को उत्पादकता, अंतर्निहित गुणवत्ता आश्वास, विशेषताओं और अंतर्निहित सुरक्षा विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक, नवीन और उच्च निष्पादन उपकरण के संबंध में चर्चा करने और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। ऊर्जा बचत (ऊर्जा क्षमता), सामग्री संसाधनों बचत (दीर्घकालिकता) और पर्यावरण संरक्षण (हरित प्रौद्योगिकियों) की चिंताओं के बारे में भी चर्चा हुई। सम्मलेन में उपकरण प्रचालकों के कौशल स्तर को परिभाषित करने और प्रचालक कौशल के प्रमाणन की पद्धति तैयार करने की आवश्यकता पर भी विचार किया गया।
- iv) मंत्रालय ने सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके कौशल विकास मंत्रालय और ठेकेदारों के माध्यम से राजमार्ग क्षेत्र में कार्यरत मुख्य उपकरण प्रचालक को कौशल प्रदान करने हेतु कार्यवाही आरंभ की है।

अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचलन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचलन प्रतिबंधित है।

Compulsory cycle track signifies that cyclists should compulsorily use this track. It also restricts the movement of any traffic accept cyclist of the track.





आईएचई में प्रशिक्षण कार्यक्रम



सड़क सुरक्षा पदयात्रा

यह चिन्ह दर्शाता है कि जिस स्थान पर यह चिन्ह लगा हुआ है वहां प्रवेश करने के पश्चात चालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएगा। इस संबंध में वंडाल्टक कार्रवाई तथा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का अनुपालन किया जाना चाहिए।

This sign indicates that vehicles using the Road, at the entrance to which the sign is placed shall travel at the specified speed. The limit specified must be Invariably followed to avoid penal action and crashes on the road.





दाहिना मोड़  
Right Hand Curve

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



रिटों – फिट बिजली बस का प्रदर्शन

यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ विखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने में सहायक होता है।

This sign cautions you about a Right Hand Curve on the road ahead. This helps you in maneuvering vehicle accordingly and nullifies the possibility of crash due to sudden appearance of turn.





## अध्याय-IV

### सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा

- 4.1 घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी गहरी पैठ के कारण सड़क परिवहन, माल भाड़ा और यात्रियों दोनों की आवाजाही के लिए एक पसंदीदा और सर्वाधिक किफायती साधन माना जाता है। इस प्रकार, देश के आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2011-12 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4.8% के हिस्से के साथ सड़क परिवहन, भारत के परिवहन क्षेत्र में एक अग्रणी घटक के रूप में उभरा है। फिर भी, 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, कुल सड़क नेटवर्क का 1.58 प्रतिशत है, इस पर कुल सड़क यातायात के 40 प्रतिशत यातायात की दुलाई होती है। सड़क यातायात अपनाए जाने के कुछ प्रमुख कारक हैं - आसान उपलब्धता, अलग-अलग प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलता और किफायती लागत। रेल, नौवहन और हवाई यातायात के लिए सड़क परिवहन, पूरक सेवा का कार्य भी करता है। वर्ष 2002 से 2012 की अवधि के दौरान पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या में 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई है। सड़क और रेल द्वारा कुल यातायात आवागमन में सड़क यातायात का हिस्सा, 1950-51 में माल यातायात के 13.8 प्रतिशत और यात्री यातायात में 15.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में माल यातायात में 64.5 प्रतिशत और यात्री यातायात में 85.9 प्रतिशत हुआ है।
- 4.2 यह मंत्रालय, पड़ोसी देशों के साथ वाहनों के आवागमन की व्यवस्था करने/इसकी मॉनीटरिंग करने के अतिरिक्त देश में सड़क परिवहन के विनियमन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
- 4.3 मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग में निम्नलिखित अधिनियमों/नियमावलियों, जिनमें मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीति निहित है, का प्रशासन किया जाता है -
- मोटर यान अधिनियम, 1988
  - केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
  - सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
  - वाहक अधिनियम, 1865 को निरस्त करके सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007
  - सड़क द्वारा वहन नियमावली, 2011
- 4.4 मंत्रालय ने 148 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मोटर वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के राज्यीय और राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने की एक परियोजना को संस्वीकृत किया है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा इस परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है। इस परियोजना में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/राज्यीय परिवहन प्राधिकरणों का कंप्यूटरीकरण किया जाना और तत्पश्चात् उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के राष्ट्रीय और राज्यीय रजिस्टर से जोड़ा जाना है। स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1006 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं जिनमें से 1001 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। राज्य की अपेक्षानुसार मानक सॉफ्टवेयर को प्रयोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप बनाने का कार्य सभी 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा किया गया है और यह सॉफ्टवेयर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम 1 प्रायोगिक स्थल में चालू है। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 100% कंप्यूटरीकरण हो चुका है और

जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना रहती है। यह चिन्ह ड्राइवर को सतर्क रहने का संकेत देता है क्योंकि आगे का रास्ता संकरा है।

When the width of the road decreases and the road merges into a narrow road, there is a possibility that a speeding vehicle may collide with oncoming traffic. This sign cautions the driver to be careful as the road ahead is narrow.





आगे रास्ता चौड़ा है  
Road Widens Ahead



- 994 आरटीओ को उनसे जोड़ दिया गया है। वाहन रजिस्टर पर वाहनों की संख्या 5 नवम्बर, 2012 को सौ मिलियन को पार कर गई है। सभी ड्राइविंग लाइसेंसो/पंजीकरण प्रमाणपत्रों के सूक्ष्म सत्यापन को बढ़ावा देने के लिए राज्य परिवहन विभाग अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन प्राधिकारियों को राष्ट्रीय रजिस्टर के संबंध में आंकड़ों के लिए पहुँच उपलब्ध कराई गई है जिसे उनके पंजीकृत मोबाइल नं. से एसएमएस भेज कर डिजिटाइज्ड किया गया है। इसके बाद 31.01.2016 की स्थिति के अनुसार डिजिटाइज्ड आरसी और डीएल के आंकड़े क्रमशः 17,50,42,055 और 8,80,54,602 हैं। वाहन पंजीकरण और परमिट पद्धति 'वाहन' को नागरिक केन्द्रित सर्वोत्तम सेवा के लिए 'प्लेटिनम आइकन वेब रत्न अवार्ड' दिया गया था।
- 4.5 वर्तमान समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़क द्वारा परिवहन व्यापार की प्रक्रिया को सुचारु बनाए जाने की दृष्टि से 'सड़क द्वारा वाहन अधिनियम 2007' को विनियमित किया गया था। यह 01 मार्च, 2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों के सुगम अनुपालन के लिए, सड़क द्वारा वाहन नियमावली, 2011 की अधिसूचना, 28.02.2011 की जीएसआर सं. 176(अ) के द्वारा जारी की गई। यह अधिनियम/नियमावली, मंत्रालय की वेबसाइट <http://morth.nic.in> पर भी उपलब्ध है। सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों से इस मंत्रालय द्वारा सड़क द्वारा वाहन नियमावली, 2011 के साथ-साथ सड़क द्वारा वाहन अधिनियम, 2007 का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय, एनआईसी द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से सड़क द्वारा वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन केरियरों के आनलाइन पंजीकरण और भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से भुगतान किए जाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। इस संबंध में 24 राज्यों ने भारतीय स्टेट बैंक में पहले ही समर्पित खाते खोल लिए हैं।
- 4.6 इस कठिनाई को दूर करने और ई-रिक्शा तथा ई-कार्ट चलाना सुगम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के भाग 7 के उपभाग (1) में संशोधन किया है जिससे केवल ई-रिक्शा और ई-कार्ट चालकों को छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम के तहत ई-रिक्शा और ई-कार्ट की परिभाषा भी इसमें शामिल की गई है। मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली में ई-रिक्शा और इसके विनिर्देशनों को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (सीएमवीआर) में संशोधन करने के लिए जीएसआर 709(ई) दिनांक 8.10.2014 का.आ. 2590 (ई) दिनांक 8.10.2014 और जीएसआर 27 (ई) दिनांक 13.01.2015 को अधिसूचित किया गया है। जिसे, मंत्रालय की वेबसाइट <http://morth.nic.in> पर अपलोड किया गया है। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में ई-रिक्शाओं को नियमित करने हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं का उल्लेख है।
- 4.7 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मोटर यान अधिनियम, 1988 के स्थान पर "सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2015" नामक नया अधिनियम लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के लिए बुरी आदतों को दूर करने और परिवहन प्रणाली का कुशल उपयोग करने का प्रस्ताव है। इसमें परिवहन क्षेत्र में कुशलता में सुधार लाने के लिए मल्टी मॉडल समन्वयन अथॉरिटी लाने का भी प्रस्ताव है। सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक 2015, दिनांक 4 जून, 2015 को सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों की टिप्पणियों/विचार जानने के लिए भेजा गया था। आज की तारीख तक लगभग 26 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक 2015, को मंत्रालय की वेबसाइट <http://morth.nic.in> पर अपलोड किया गया है।

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार, यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए।





- 4.8 माल वाहनों की अंतर राज्य आवाजाही सुकर करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 8 मई, 2010 से माल ढुलाई के लिए नई राष्ट्रीय परमिट पद्धति शुरु की गई है। नवीन प्रबंधों के अनुसार, देश भर में प्रचालन के लिए परमिट धारक को प्राधिकृत करने के लिए गृह राज्य अधिकारिता फीस के रूप में 1000 /- रूपए और एक समेकित फीस के रूप में प्रति ट्रक 16,500 रूपए के वार्षिक भुगतान पर राष्ट्रीय परमिट गृह राज्य द्वारा जारी किया जा सकता है। दिनांक 15.09.2010 से नेशनल इनफोर्मेटिक सेंटर (एन.आई.सी) द्वारा विकसित वेब पोर्टल के माध्यम से नई पद्धति को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा संग्रहीत समेकित फीस, एक सहमत फार्मूला आधारित यथानुपात आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सवितरित की जाती है।
- 4.9 वर्ष 2015-16 के दौरान, केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे और इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज आफ इंडिया, हैदराबाद, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान, फरीदाबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और पेट्रोलियम संरक्षण और रिसर्च एसोसिएशन दिल्ली नामक प्रमुख ऑटोमोबाइल संस्थानों/रिसर्च एसोसिएशन और शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से राज्य परिवहन/यातायात विभागों और नगर निगम के अधिकारियों के लिए इस मंत्रालय द्वारा 54 कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे इसमें भाग लेने वालों के सड़क परिवहन क्षेत्र में शासन और उभरती चुनौतियों का सामना करने के सभी पहलुओं की जानकारी दी जा सके।



- 4.10 केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 59 केन्द्र सरकार के वाहनों की आयु निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है। परिवहन वाहनों और पर्यटन वाहनों की जीवन अवधि सीएमवीआर द्वारा निधारित की गई है। व्यक्तिगत वाहनों की जीवन अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इस संबंध में नीतिगत निर्णय देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर लिया जाना है। सामान्यतः, वाहन को सुरक्षा और उत्सर्जन मानदंड पूरे किए जाने तक सड़क पर चलने के लिए अनुमत किया जाना चाहिए। सुरक्षा और उत्सर्जन अपेक्षा तभी पूरी की जा सकती है जब वाहन की फिटनेस जांच नियमित अंतराल पर कराई जाए। अतः मंत्रालय ने वाहनों के लिए एक उपयुक्त/ डिजाइन की गई निरीक्षण और अनुरक्षण पद्धति तैयार की है। तदनुसार, देश में एक आटोमेटिड इन्स्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन (आईएससी) सेंटर का डिजाइन तैयार किया गया।

यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन-भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह दिखने पर चालक सदैव बुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करे।

This sign indicates the slippery condition of the road ahead. This condition could be due to seepage of water or oil spill etc. The driver should invariably slow down the vehicle at sight of this sign to avoid crash.





## साइकिल क्रॉसिंग Cycle Crossing



- 4.11 मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों जैसी संरचनात्मक परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के उद्देश्य से ओवर ड्राइमेंशनल कार्गो (ओडीसी) और ओवर वेट (ओडब्ल्यूसी) के आवागमन हेतु मार्गनिर्देश परिचालित किये हैं। इन मार्गनिर्देशनों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओडीसी और ओडब्ल्यूसी चलाने वाले ट्रान्सपोर्टर्स को सूचीबद्ध परामर्शदातओं के माध्यम से पुलों की स्थिति सर्वेक्षण देने के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। भार भी अनुमत सीमा तक ही लादना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने अनुमति के लिए आवेदनों की ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत 6.62 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है। राज्यवार अनुमति का बास-चार्ट परिशिष्ट-6 पर दिया गया।

## सड़क सुरक्षा

- 4.12 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में सड़क सुरक्षा मुद्दों, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस की स्थापना किए जाने, ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाये जाने, सड़क सुरक्षा कानूनों के बेहतर प्रवर्तन इत्यादि के संबंध में जागरूकता प्रदान करने पर बल दिया गया है। मंत्रालय द्वारा प्रचालित सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण योजना में सड़क सुरक्षा पर प्रचार, उपाय और जागरूकता अभियान, ड्राइविंग प्रशिक्षण हेतु संस्थानों की स्थापना करने की योजना असंगठित क्षेत्र में ड्राइवरों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना और मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा स्कीम (एनएचएआरएसएस), निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करना और सड़क सुरक्षा तथा प्रदूषण प्रशिक्षण उपकरण इत्यादि जैसी स्कीमें शामिल हैं।



सड़क सुरक्षा प्रदर्शन

यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को सावधानीपूर्वक चौराहा (इंटरसेक्शन) पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सकें।

This road sign indicates that there is a cycle path intersecting the major road or is frequented by cyclists. The driver should carefully cross this intersection so that cyclist could cross the major road safely.